शिक्षा का बेड़ा ग़र्क़ न होने देना, हमारी ज़िम्मेदारी है

सत्यवीर सिंह

बाक़ी मामलों की ही तरह, देश में शिक्षा का सत्यानाश करने की शुरुआत 2014 में मोदी सरकार आने के बाद से नहीं हुई. इसकी शुरुआत तो, कांग्रेस के शासन काल में, 1991 में ही हो गई थी. जब देश के पूंजीवादी 'विकास' की तत्कालीन ज़रूरत के अनुसार, ढोल-ढमाकों से 'उदारीकरण-निजीकरण-वैश्वीकरण' की देश-व्यापी लहर पैदा की गई थी, जिसे देश की सभी बीमारियों की राम-बाण बूटी बताया गया था. भाड़े के बुद्धिजीवियों ने जिसके क़सीदे पढ़ते हुए लम्बे-लम्बे लेख लिखे थे, कि इससे देश में ग़रीबी मिट जाएगी, चहुँ ओर खुशहाली फ़ैल जाएगी, असली आज़ादी तो अब आएगी!! टुकड़खोर मीडिया, दिन-रात कीर्तन में जुट गया था. पहले से बीमार पूंजीवाद, 1991 के इंजेक्शन से भी पहलवान नहीं बना. बल्कि, कंगाली और भुखमरी हर ओर पसर गई. उसके बाद, पूंजीवादी संकट की 2008 की तबाही और ज्यादा भयानक थी. चूँकि, पूंजी का वैश्वीकरण हो चुका था, संकट भी घनघोर रूप से विश्वव्यापी बन गया.

देश के शासक वर्ग, मतलब अडानी-अम्बानियों, टाटा- बिड़लाओं ने, अपनी ताबेदार सरकार से देश के हर क्षेत्र को उन्हें लूटने की स्वच्छंद छूट देने की मांग की. पूंजीवाद में सरकार किसी भी पार्टी की हो, उनका झंडा किसी भी रंग और डिजाईन का हो, होती वे कॉर्पोरेट की मैनेजमेंट कमेटियां ही हैं. हुक्म की तामील करते हुए, कांग्रेस की सरकार, 2009 में 'शिक्षा के अधिकार का क़ानून, लेकर आई. 'शिक्षा के अधिकार का क़ानून'; पढ़कर लगेगा, मानो देश के ग़रीब बच्चों को शिक्षा का अधिकार देने की बात होगी, लेकिन उसका असल मक़सद इसके ठीक उलट था- शिक्षा की दुकानें खोले बैठे सरमाएदारों को मनमाने ढंग से फ़ीस बढ़ाने की छूट देना, शिक्षा के क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देना, शिक्षा को बाज़ार या उद्योग बना डालना, शिक्षा में असमानता, मतलब, जितना जेब में पैसा वैसी शिक्षा, स्कूल आर्थिक कठिनाई में आ जाएँ उन्हें बंद कर देने का प्रावधान, सरकारी मदद कम करते जाना, शिक्षा का उद्देश्य मानव विकास ना होकर, जैसे-तैसे गुजारे का ज़रिया बना डालना. 'विश्व व्यापार संगठन (WTO)' की शर्तों के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र को देश की पूंजी के लिए ही नहीं, बल्कि विदेशी पूंजी के लिए भी खोल देना. 'शिक्षा का अधिकार, 2009' क़ानून ने शिक्षा जगत को झकझोर दिया.

शिक्षा के भविष्य, मतलब समाज के भविष्य के प्रति गंभीर चिंता का ही नतीज़ा था कि देश के जाने-माने और दृढ सामाजिक सरोकार रखने वाले शिक्षाविदों ने इस विषय पर एक सम्मलेन करने का फैसला किया. 'शिक्षा हो सबका मूल अधिकार तथा राष्ट्रपति से चपरासी तक सभी के बच्चों को केजी से पीजी तक समान व निशुल्क शिक्षा' लागू कराने के उद्देश्य से, देश के प्रतिष्ठित शिक्षाविदों का दो-दिवसीय सम्मलेन हैदराबाद के ओस्मानिया विश्वविद्यालय में, 21 व 22 जून 2009 को सम्पन्न हुआ था.

उस मंथन से, 'अखिल भारतीय शिक्षा अधिकार मंच', All India Forum for Right To Education, AIFRTE'), नाम की एक संस्था वजूद में आई. आज देश के 22 राज्यों में इस मंच की शाखाएँ अपने मिशन में लगी हुई हैं. छात्रों, अध्यापकों, ट्रेड यूनियनों, मानवाधिकारों के 100 से भी अधिक संगठन इससे जुड़े हुए हैं. एआईएफआरटीई के तीन आधारभूत सिद्धांत हैं.

1) शिक्षा; व्यापार, निजी अथवा विदेशी निवेश द्वारा मुनाफ़ा कूटने का क्षेत्र नहीं है.

2) देश के सभी छात्रों को शुरू से अंत तक, निशुल्क एवं एक समान शिक्षा, मतलब राष्ट्रपति हो या चपरासी, मालिक हो या मज़दूर, सबके लिए 'केजी से पीजी तक' एक जैसी शिक्षा की व्यवस्था करना, सरकार की संवैधानिक ज़िम्मेदारी है.

3) शिक्षा का उद्देश्य है; जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी समाज बनाना जो विविधताओं, विभिन्नताओं और बराबरी की बुनियाद पर खड़ा हो.

आर्थिक संकट पूंजीवाद को उसकी क़ब्र में धकेलता गया जिसे मौत से बचाने के लिए, कांग्रेस ने सभी क्षेत्रों में घोर जन-विरोधी और नंगे तौर पर कॉर्पोरेट परस्त नीतियाँ लागू कीं, लेकिन, इज़ारेदार बड़े कॉर्पोरेट मगरमच्छ, जो पूंजी के पहाड़ पर बैठे थे, उसकी गति से संतुष्ट नहीं हुए. वे चाहते थे कि सारे नियम-कायदों, मज़दूर कानूनों, संवैधानिक अधिकारों को पैरों तले कुचलकर, देश के सारे संसाधनों को उन्हें तुरंत निगलने दिया जाए. शिक्षा हो या कृषि, सारा देश उनके शिकार के लिए खुला छोड़ दिया जाए. पूंजीवाद-साम्राज्यवाद ने, अब, फासीवादी रास्ते को चुन लिया था. मीडिया शोर मचाने लगा, नीतिगत पक्षाघात (policy paralysis) की वज़ह से 'विकास' रुक गया है.

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को, जो उस वक्त तक कॉर्पोरेट के लाडले थे, क्योंकि उनके वित्त मंत्री रहते हुए 'नवउदारवादी' लूट के युग का सूत्रपात हुआ था, अब 'मनमौन सिंह' लिखा जाने लगा, उन्हें कमजोर बताया जाने लगा. 'महाभ्रष्टाचार' के किस्से महालेखाकार की ओर से आने लगे. अन्ना हजारे एकदम नाटकीय अंदाज़ में प्रकट हुए और रातोंरात हीरो बन गए. 'डायनामिक लीडर' की तलाश शुरू हुई. 'गुजरात मॉडल' को लोकप्रिय बनाया गया और 2014 में देश को 'डायनामिक लीडर' के रूप में मोदी जी प्राप्त हुए. मोदी सरकार ने, अपने अजेंडे के अनुसार, किसान, मज़दूर के साथ ही शिक्षा को भी निशाने पर लिया और 'नई शिक्षा नीति, 2020' संसद से मंजूर हुई. शिक्षा के व्यवसायिकरण, निजीकरण का सफ़र जो 'शिक्षा के अधिकार, 2009' से शुरू हुआ था 'नई शिक्षा नीति, 2020' से टॉप गियर में दौड़ने लगा. शिक्षा के व्यवसायिकरण व निजीकरण के साथ, अब भगवाकरण भी जुड़ गया. मोदी सरकार, चूँकि, 'डायनामिक' है, इसलिए उसकी गति कांग्रेस सरकार से भिन्न है!!

जुझारू शिक्षा आन्दोलन खड़ा करने के लिए राष्ट्र स्तरीय चर्चा शिक्षा के मूल तत्वों को बचाने के लिए प्रतिबद्ध, देश के प्रतिष्ठित शिक्षाविदों को फिर से एक राष्ट्रस्तरीय की चर्चा करने की ज़रूरत महसूस हुई, और 30 सितम्बर से 01 अक्टूबर को, कॉमरेड सुरजीत भवन, कॉमरेड इन्द्रजीत गुप्ता मार्ग, नई दिल्ली में दो दिवसीय चर्चा सम्मलेन संपन्न हुआ, जिसमें कुल 60 संगठनों को आमंत्रित किया गया था जिनमें 'क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा, फरीदाबाद' भी शामिल था. ढ्ढस्नक्रञ्जश्व के चेयरमैन प्रोफ़ेसर जगमोहन सिंह, सांगठनिक मंत्री प्रो विकास गुप्ता, प्रो राजगोपाल, डॉ गंगाधर, प्रो मधु प्रसाद, प्रो चंद्रधर राव, प्रो राममूर्ति, असम से आईं प्रो इन्द्राणी, मध्य प्रदेश के आदिवासियों में कार्यरत श्रीमती माधुरी जी के आलावा देश भर से आए लगभग 60 प्रतिनिधियों ने, इस दो दिवसीय गहन चर्चा में खुलकर भाग लिया. पहले दिन, प्रत्येक डेलिगेट को 8 मिनट में ही अपनी बात रखनी थी. विभिन्न राज्यों से आए प्रतिनिधियों ने शिक्षा आन्दोलन के समक्ष जिन प्रमुख चुनौतियों को रखा, वे इस तरह हैं.

शिक्षा का व्यवसायीकरण, भगवाकरण, केन्द्रीकरण (सारे फैसले केंद्र ही लेगा), सरकारी स्कूलों का लगातार बंद अथवा विलय करना, शिक्षकों की भर्ती ना करना और अगर करनी ही पड़े तो ठेके पर करना, शिक्षा के पाठ्यक्रम को क्रमबद्ध तरीक़े से विकृत करना, तर्कपूर्ण, वैज्ञानिक एवं धर्मनिरपेक्ष विचार व दृष्टिकोण पैदा करने वाले अध्यायों की जगह मनगढ़ंत, तर्कहीन, अंध विश्वास पर आधारित विचार लाकर बच्चों की कोमल मानसिकता को विकृत करना, इतिहास के मूल तत्व को विषाक्त कर कपोलकल्पित गपोड़ों को इतिहास बताते हुए, प्राचीन भारत के एक विशिष्ट काल को ज़बरदस्ती 'स्वर्णिम युग' घोषित करना, महान क्रांतिकारियों को भी किसी विशिष्ट धर्म से जोड़ने की हिमाक़त करना, इतिहास को इस तरह प्रस्तुत करना जिससे अल्पसंख्यकों के प्रति क्रोध और नफ़रत पैदा हो, 'गौ विज्ञान, गोबर विज्ञान, गोमूत्र उपचार पद्धति, वैदिक गणित, कर्मकांड में डिप्लोमा आदि' बेहूदगियों को वैज्ञानिक बताते हुए प्रचारित करना और शोध के नाम पर इन्हीं विषयों को सरकारी कोष उपलब्ध कराना, किसी भी वैज्ञानिक शोध के लिए छात्रवृत्ति के लिए कोई भी पैसा ना देना, कोलकता से आए छात्र प्रतिनिधि ने बताया कि कैसे पीएचडी कर रहा एक छात्र छात्रवृत्ति की मदद ना मिलने के कारण आत्म हत्या को मज़बूर हुआ, जबकि 'गौ विज्ञान' के प्रसार के लिए 21 करोड़ रुपये की मदद विश्वविद्यालय कोष में पड़ी हुई है, शिक्षा की सभी मदों, जैसे ट्यूशन फीस, परीक्षा फीस, हॉस्टल फीस आदि को इतना बढ़ा देना कि देश के 80 प्रतिशत आम ग़रीब किसान-मज़दूरों के बच्चे शिक्षा संस्थानों में जाने लायक ही ना बचें,

शिक्षा से सम्बद्ध सभी पदों पर, नियम-आधारित चयन तथा पदोन्नति प्रक्रियाओं को दरकिनार कर, सत्तारूढ़ भाजपा समर्थकों-पदाधिकारियों और विशुद्ध संघी प्रचारकों को नियुक्त करना, शिक्षा समवर्ती सूचि में होने के बावजूद, सारे फैसले केंद्र सरकार के आधीन करते जाना और संघीय ढांचे की बुनियाद को ही खोखला कर डालना, देश ने भाषा के सवाल पर विघटनकारी हिंसक आन्दोलन झेले हैं,

इस तथ्य को नज़रंदाज़ कर ग़ैर-हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी थोपने सम्बन्धी बयान ज़ारी करना जिससे विघटनकारी आन्दोलन चलाने वालों को प्रोत्साहन मिले, व्यवसायिक शिक्षा के नाम पर बढईगिरी, प्लंबरी आदि में उलझाकर आम-ग़रीब बच्चों को शिक्षा द्वारा अपने व्यक्तित्व को विकसित करने के अवसर से ही महरूम कर डालना, ऑनलाइन-डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना, भले देश के आम लोगों के बच्चे, सुविधा ना होने के कारण शिक्षा से बाहर ही क्यों ना हो जाएँ, जिनके सामने खुद को उद्योगों के लिए सस्ते श्रम के रूप में प्रस्तुत करने के सिवा कोई विकल्प ही ना बचे, विश्वविद्यालयों में मुक्त वैचारिक डिबेट करने वालों को 'अर्बन नक्सल' घोषित कर, दमनचक्र चलाना, विश्वविद्यालीय वातावरण को विषाक्त करना, नई शिक्षा नीति 2020 को ज़बरदस्ती थोपना, जबकि कोरोना काल में लाई गई इस जन-विरोधी नीति पर देश में कोई बहस हुई ही नहीं है, आदि.

हरियाणा में शिक्षा का हाल

'क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा, फरीदाबाद' के आलावा 'परिवर्तनकामी छात्र संगठन', 'छात्र एकता मंच, हरियाणा' तथा 'प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स फ्रंट, हरियाणा' ने भी सम्मलेन में प्रतिनिधित्व किया. हरियाणा के लोग 'डबल इंजन' की सरकार झेल रहे हैं, इसलिए यहाँ भाजपा-संघ का शिक्षा अजेंडा भी टॉप गियर में है. हरियाणा में अध्यापकों के 38,000 पद रिक्त हैं.

उन्हें भरने की बजाए हरियाणा सरकार ने अध्यापकों के 20,000 पदों को ही समाप्त कर दिया गया. पिछले एक साल में, प्रदेश में 301 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए हैं. 19 अगस्त को, एक ही दिन में 105 स्कूल बंद कर दिए गए. बड़े पैमाने पर स्कूलों को बंद करने या दूसरे में मिला देने की सरकारी योजना है, जिसके लिए ये तर्क दिया जा रहा है कि इन सरकारी स्कूलों में पर्याप्त छात्र नहीं है. इस झूठ की पोल तो खुद हरियाणा सरकार के पिछले साल के आंकड़े ही खोल देते हैं.

कोरोना काल में, बड़े पैमाने पर मज़दूर बेरोज़गार हुए और जो बे-रोज़गारी से बच भी गए, उनके भी वेतन में बहुत कटौतियां हुईं . मध्यम वर्ग के लगभग 2 लाख लोग, अपने लाड़लों को मंहगे निजी स्कूलों से निकालकर, सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलाने को मज़बूर हुए. निजी शिक्षा संस्थान, जो या तो खुद राजनीतिक नेताओं के ही होते हैं, या राजनीतिक रसूखदार लोगों के होते हैं, इन बच्चों से कोरोना काल की पूरी फ़ीस ऐंठने के चक्कर में, टीसी ज़ारी नहीं कर रहे थे. तब, हरियाणा के शिक्षण विभाग ने एक आदेश ज़ारी किया था, कि अर्जी देने के 15 दिन में अगर कोई निजी स्कूल ट्रान्सफर सर्टिफिकेट ज़ारी नहीं करता, तो उसे ज़ारी किया हुआ ही माना जाएगा. उस अर्ज़ी की कॉपी ही टीसी का काम करेगी. इस आदेश के बाद निजी स्कूलों के मालिकों की रसूखदार एसोसिएशन चंडीगढ़ उच्च नयायालय से स्थगन आदेश ले लाई और सरकार ने वह आदेश वापस ले लिया. सैकड़ों संस्थानों को 'विश्वविद्यालय' का दर्ज़ा देकर उन्हें मनमानी फ़ीस बढ़ाने तथा अध्यापकों के वेतन को घटाने की छूट दी जा रही है. विश्वविद्यालयों को सरकारी ग्रांट की जगह, क़र्ज़ लेने को बाध्य किया जा रहा है, जिसकी ब्याज सहित वसूली छात्रों से ही की जाएगी.

रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय को हाल में ऐसा ही मोटा-तगड़ा लोन मंजूर हुआ है. ज़ाहिर है कि फ़ीस जो पहले ही दस गुना तक बढ़ गई है, आगे और भी तूफानी गति से बढ़ेगी जिसके परिणामस्वरूप मज़दूर वर्ग की तो छोडिए, वह तो पहले ही अपने बच्चों को शिक्षा दे पाने लायक नहीं बचा, उच्च मध्यम वर्ग भी अपने लाड़लों को इंजिनियर या डॉक्टर बनाने लायक नहीं बचेगा. पाठ्यक्रम में हर स्तर पर 'गीता ज्ञान', 'गौ ज्ञान' देने की मुहिम जोर-शोर से चलाई जा रही है. कुरुक्षेत्र के पास गाँव में स्थित 'अमतिर कन्या गुरुकुल' हायर सेकेंडरी स्कूल में, एक अध्यापिका को सुबह 7 बजे स्कूल में रोजाना होने वाले यज्ञ में आने को मज़बूर किया गया. बच्ची छोटी होने के कारण तथा इस कर्मकांड में विश्वास ना होने की वज़ह से यज्ञ में शरीक ना हो पाने के कारण, उन्हें वेतन दिए बगैर ही नोकरी से निकाल दिया गया.

स्कूल प्रबंधन को सरकार और आरएसएस का आश्रय होने के कारण उनकी किसी भी शिकायत का कोई परिणाम नहीं हुआ. क्रांतिकारी विचारों से हरियाणा सरकार को इतनी दिक्कत है कि फरीदाबाद में 'शहीद भगतसिंह स्मारक' को तोड़ कर उसे 'विस्थापन विभीषिका स्मारक' में बदल दिया गया तथा अमर शहीद क्रांतिकारियों को विस्थापन विभीषिका से जोड़ने का दुस्साहस किया गया. हरियाणा के सभी संगठनों ने संयुक्त मोर्चा बनाकर इन सभी जन-विरोधी मुद्दों पर जन-आन्दोलन चलाने का फैसला किया. शिक्षा आन्दोलन को देशव्यापी सशक्त आन्दोलन कैसे बनाया जाए?

1) शिक्षा पर भाजपा सरकार द्वारा बोला गया हमला चौतरफ़ा है, और इसकी तीव्रता दिनोंदिन तेज़ी से बढ़ती जा रही है. सरकार अगर किसी नीति, जैसे फ़ीस वृद्धि, स्कूल बंद करने, अध्यापकों की नियुक्ति ना करने को, वापस लेने को मज़बूर हो भी जाती है, तब भी वह इसे रद्द कभी नहीं करती. बल्कि दो क़दम पीछे लेती है, और जैसे ही जन आक्रोश थोडा धीमा होता है, पहले से भी ज्यादा आक्रामक रूप में फिर आगे बढ़ जाती है. ये एक तरह का युद्ध है. इसीलिए इसकी व्याख्या करते हुए, सभी वक्ताओं ने इसे 'शिक्षा के विरुद्ध सरकारी युद्ध क़रार दिया'.

बिल्कुल ऐसा ही युद्ध मज़दूरों के विरुद्ध ज़ारी है. सदियों की कुर्बानियों से हांसिल उनके अधिकार रद्द कर उन्हें 4 लेबर कोड थमा दिए गए हैं. चूँकि मज़दूर इस हमले के विरुद्ध लामबंद हो रहे हैं, इसलिए लेबर कोड्स का कार्यान्वयन, सरकार टालती जा रही है लेकिन उन्हें रद्द नहीं कर रही. वैसे ही हालात किसानों के थे, जिन्होंने देशव्यापी ज़बरदस्त आन्दोलन कर सरकार को चौंका दिया और पहली रणनीतिक जीत हांसिल की. हालाँकि, किसान, अगर उसे निर्णायक जीत मान रहे हैं तो यह उनकी भारी भूल है. अभी कश्मीर से सेव के **शेष पेज 6 पर**